भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1929
जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2026 को दिया जाना है ।
22 माघ, 1947 (शक)

ईसीएमएस की निगरानी

1929. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः
श्री विजय कुमार दूबेः
श्री धर्मबीर सिंहः
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः
डॉ. विनोद कुमार बिंदः
श्री गोडम नागेशः
डॉ. निशिकान्त दुबेः
श्री नव चरण माझीः
श्री बंटी विवेक साहूः
श्री बिभु प्रसाद तराईः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आयात को कम करने, निर्यात वृद्धि और रोजगार सृजन के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ईसीएमएस) के अपेक्षित प्रभाव का आकलन किया है और तेलंगाना और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले पर इसके संभावित प्रभाव क्या हैं;
(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के तहत प्रस्तावित प्रमुख परिणाम संकेतक क्या हैं;
(ग) क्या सरकार द्वारा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कोई समर्पित निगरानी और मूल्यांकन तंत्र विहित किया गया है;
(घ) यदि हां, तो वर्तमान प्रगति की स्थिति सहित तंत्र और इसके कार्यान्वयन के लिए संस्थागत क्रियाविधि का विशेषकर मध्य प्रदेश में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) तेलंगाना राज्य और मध्य प्रदेश के विशेषकर औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों जैसे छिंदवाड़ा में निवेश और विनिर्माण समूहों को प्रोत्साहित करने की योजनाओं सहित ईसीएमएस के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण को बढ़ाने के लिए क्या रूपरेखा है; और
(च) क्या भिवानी-महेंद्रगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में युवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण और तकनीकी इंटर्नशिप के अवसरों का विस्तार किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): माननीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, भारत का लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र के लिए संपूर्ण विनिर्माण इकोसिस्टम विकसित करना है। पिछले 11 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में काफी विस्तार हुआ है, जैसा कि नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

#	2014-15	2024-25	टिप्पणियां
इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं का उत्पादन (रु.)	~1.9 लाख करोड़	~11.3 लाख करोड़	6 गुना वृद्धि
इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं का निर्यात (रु.)	~0.38 लाख करोड़	~3.3 लाख करोड़	8 गुना वृद्धि
मोबाइल फोनों का उत्पादन (रु.)	~0.18 लाख करोड़	~5.5 लाख करोड़	28 गुना वृद्धि
मोबाइल फोनों का निर्यात (रु.)	~0.01 लाख करोड़	~ 2 लाख करोड़	127 गुना वृद्धि

इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण इकोसिस्टम को और सुदृढ़ और व्यापक बनाने के लिए, सरकार ने अप्रैल 2025 में **इलेक्ट्रॉनिकी घटक विनिर्माण योजना (ईएसएमएस)** शुरू की। इस योजना का उद्देश्य मूल्य श्रृंखला में निवेश (वैश्विक/घरेलू) को आकर्षित करके सुदृढ़ घटक विनिर्माण इकोसिस्टम विकसित करना है, जिससे घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) में वृद्धि हो और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) के साथ अपने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को एकीकृत करके वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में भारत के निर्यात की हिस्सेदारी में वृद्धि हो।

इस योजना के तहत भारत में घरेलू/वैश्विक निर्माताओं से 59,350 करोड़ रुपये के निवेश, 4,56,500 करोड़ रुपये के उत्पादन और 91,600 रुपये के अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोजगार की परिकल्पना की गई थी।

इस योजना को अब तक उद्योग से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली है। 59,350 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश की तुलना में 1.15 लाख करोड़ रुपये के निवेश मूल्य वाली परियोजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं।

ईसीएमएस को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी), पैसिव कम्पोनेंट, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल घटकों, उप-असेंबली, कैमरा मॉड्यूल, ऑप्टिकल ट्रांसीवर और इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत सामान जैसे प्रमुख घटकों के घरेलू विनिर्माण की क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन घटकों का उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करेगा और इनमें से कई घटकों के लिए निर्यात क्षमता में भी वृद्धि करेगा।

ईसीएमएस योजना एक अखिल भारतीय पहल है, और विनिर्माण इकाइयों का स्थान उद्योग द्वारा तय किया जाता है।

अब तक 11 राज्यों में कुल 46 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। इनसे 54,567 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है, जिससे 3,67,343 करोड़ रुपये का अनुमानित उत्पादन होगा और योजना अवधि के दौरान 50,794 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार अनुमानित है।

ईसीएमएस योजना इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) नामक एक कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। पीएमए प्रस्तावों की जांच करता है और गवर्निंग काउंसिल (जीसी) को यथोचित सिफारिशें करता है। जीसी एक अंतर-मंत्रालयी परिषद है जिसकी अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव करते हैं और इसमें नीति आयोग, व्यय विभाग, आर्थिक मामलों के विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, दूरसंचार विभाग और भारी उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। जीसी प्रस्तावों की समीक्षा करता है और यथोचित सिफारिशें करता है।

इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा बनाने हेतु, एमईआईटीवाई ने निम्नलिखित को मंजूरी दी है:

- तेलंगाना में ई-सिटी (हैदराबाद), महेश्वरम (रंगारेड्डी), डिविटिपल्ली (महबूबनगर) और रायदुर्ग गांव (हैदराबाद) में 1 कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) में 3 इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी)
- मध्य प्रदेश में बड़वाई (भोपाल) और पुर्वा (जबलपुर) में 2 ईएमसी।

ये क्लस्टर तैयार भूमि, उपयोगिताओं और सामान्य सुविधाओं के साथ प्लग-एंड-प्ले विनिर्माण बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं, सेटअप समय को कम करते हैं और उत्पादन दक्षता में वृद्धि करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिकी में निवेश को आकर्षित करने के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार करेगा।

(च): हरियाणा के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट), एमईआईटीवाई के तहत एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसायटी का अपना केंद्र कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा, नाइलिट के पास हरियाणा राज्य में डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रमों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 300 से अधिक सुविधा केंद्र हैं, जिनमें से 12 सुविधा केंद्र भिवानी में और 5 सुविधा केंद्र महेंद्रगढ़ में स्थित हैं। पिछले 3 वर्षों से, हरियाणा राज्य में कुल 19,169 उम्मीदवारों को नाइलिट डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रमों में कुशल बनाया गया है, जिनमें से 1146 और 956 उम्मीदवार क्रमशः भिवानी और महेंद्रगढ़ जिलों से हैं।

*****